(ङ) लगी पूंजी पर 5 प्रतिशत का निवल लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की संख्या 45 थी।

औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश

4330. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक क्षेत्र में हुए कुल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत भाग सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगा है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1997-98 के लिए इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन उद्योगों ने इनमें किये गये पूंजी निवेश के पांच प्रतिशत के बराबर भी लाभ नहीं कमाया है; और

(घ) यदि हां, तो इन्होंने कितने प्रतिशत लाभ कमाया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार, जिस अवधि के लिए सूचना उपलब्ध है, औद्योगिक प्रतिष्ठान जोकि विभागीय उपक्रमों सहित सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, इनमें औद्योगिक क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश का लगभग 31 प्रतिशत निवेश किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने लगाई गई पूंजी पर प्रतिशत के रूप में 5.1 प्रतिशत लाभ अर्जित किया था।

स्वरोजगार हेतु खादी ग्रामोद्योग द्वारा ऋण दिया जाना

4331. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री नागमणि:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को स्वरोजगार दिलाने हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए खादी ग्रामोद्योग द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नई योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खादी और ग्रामोद्योग की परियोजनाएं किसी भी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा आरंभ की जा सकती हैं। तथापि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और विकलांगों के मामले में दिया जाने वाला अनुदान अन्य वर्गों से अधिक होता है।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों वर्ग के अंतर्गत रोजगार के राज्य-वार अनंतिम ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है (नीचे देखिये)। तथापि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अन्य वर्गों के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अ०जा०/अ०ज०जा० के सर्वाधिक लाभानुभोगी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत चमड़ा उद्योग के विभिन्न कार्यकलापों में संकेन्द्रित है। इस उद्योग के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ऐसे स्थानों पर परियोजनाएं क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है जहां पर अनुसूचित जाति के चमड़े के कार्य के दस्तकारों की बहुलता हो। प्रारंभ में यह विचार था कि 200 परियोजनाएं स्थापित करके 2.00 लाख दस्तकारों को रोजगार प्रदान किया जाए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सीमांत धन योजना के अंतर्गत अ०जा०/अ०ज०जा०, अन्य पिछड़े वर्ग और विकलांग वर्गों के लाभानुभोगी को अतिरिक्त 5 प्रतिशत सीमांत धन प्रदान किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगारों की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	(लाख व्यक्ति) कुल खादी और ग्रामोद्योग रोजगार	(लाख व्यक्ति) अनुसूचित जाति/ जनजाति का भाग
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.74	1.19
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	1.16	0.37
4.	बिहार	3.58	1.14
5.	गोवा	0.06	0.01
6.	गुजरात	1.10	0.35
7.	हरियाणा	0.96	0.30

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	0.96	0.30
9.	जम्मू और कश्मीर	0.87	0.27
10.	कर्नाटक	2.05	0.65
11.	केरल	2.21	0.70
12.	मध्य प्रदेश	1.29	0.41
13.	महाराष्ट्र	4.97	1.59
14.	मणिपुर	0.44	0.14
15.	मेघालय	0.13	0.04
16.	मिजोरम	0.11	0.03
17.	नागालैण्ड	0.18	0.05
18.	उड़ीसा	2.14	0.68
19.	पंजाब	1.89	0.60
20.	राजस्थान	4.20	1.34
21.	सिक्किम	0.04	0.01
22.	तमिलनाडु	11.85	3.79
23.	त्रिपुरा	0.27	0.08
24.	उत्तर प्रदेश	11.93	3.81
25.	पश्चिम बंगाल	3.74	1.19
26.	संघ शासित प्रदेश	-	-
1.	अण्डमान और निकोबार	-	-
2.	चंडीगढ़	0.13	-
3.	दादरा और नागर हवेली	-	-
4.	दमन और द्वीव	-	-
5.	दिल्ली	0.21	0.06
6.	लक्ष्यद्वीप	-	-
7.	पांडिचेरी	0.04	0.01
		60.15	19.11

टिप्पणी = 500 से कम

औद्योगिक विकास

4332. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में हुए औद्योगिक विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल औद्योगिक उत्पादन में क्रमश: भारतीय कंपनियों तथा विदेशी सहयोग प्राप्त कंपनियों का हिस्सा कितना-कितना है; और

(ग) भारतीय कंपनियों ने उदारीकरण के बाद किन-किन क्षेत्रों में अधिकतम विकास दर प्रदर्शित की है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 1993-94, 100%) के अनुसार वर्ष 1995-96, 1996-97, और 1997-98 में औद्योगिक वृद्धि की दरें क्रमश: 12.7%, 5.6% और 6.2% थीं। 1997-98 के दौरान विकास दर में सुधार हुआ, क्योंकि यह दर 1996-97 के 5.6% की तुलना में 6.2% हो गई।

(ख) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भारतीय कंपनियों और विदेशी सहयोग वाली कंपनियों का योगदान शामिल है किन्तु, अलग-अलग ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते।

(ग) वे क्षेत्र, जिनमें 1992-93 से औसतन ऊंची वृद्धि दर (8 प्रतिशत से अधिक) दर्ज की गयी है, ये हैं- मोटर साइकिलें, कारें, खुदाई के उपकरण, पोत निर्माण, व्यावसायिक वाहन, बिजली के पंखे और मशीनें के औजार।

PSUs in Punjab

4333. SHRI LAJPAT RAI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of PSUs in Punjab;

(b) the number of PSUs making profits;

(c) the reasons for sickness of the rest;

(d) what is the burden of administrative workers in service separately unit-wise;

(e) the plans of Government about sick units; and

(f) by when Government will determine the future of sick units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL):

(a) and (b) Semiconductor Complex Ltd. (SCL) is the only CPSu having its registered office in the State of Punjab. SCL had made profit of Rs 8.35 crores in the last five years from 1992-93 to 1996-97 and is not a sick company.

(c) to (f) Does not arise.

Representation against Mou signed with Suzuki

4334. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state: